Mrs. Nidhi Shri Shukla

Department of commerce

Paper Published:

- 5 Research Papers published in UGC reffered journal's.

S.No.	TITLE OF PAPER	NAME OF JOURNAL	YEAR OF PUBLICATION	ISBN/ISSN NUMBER
1	भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी एवं सहयोग की भूमिका	Naveen shodh sansar	Vol-I, jan to mar 2015	ISSN-2320-8767 & E-ISSN-2394-3793
2	भारत की गरीबी निवारण योजनाओं का मूल्यांकन	Naveen shodh sansar	Vol-IV, jan to mar 2018	ISSN-2320-8767 & E-ISSN-2394-3793
3	Contribution of industrial sectors in corporate social responsibility	JASRAE, GNITED MIND Journal	Vol-15 issue-I, Apr 2018	ISSN-2230-7540
4	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं भारत	Naveen shodh sansar	Vol-III, April 2018	ISSN-2320-8767 & E-ISSN-2394-3793
5	Skill development programme and self-employment opportunity in Chhattisgarh.	Divya shodh samiksha	Vol-I, Oct-Dec 2019	ISSN-2394-3807 E-ISSN-2394-3513

Volume I, E - Journal
Jan. to March 2015

Reg. No. MPHIN/28519/12/1/2012-TC
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 0.715 (2014)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

28. The Best Approach To Environmental Management Is An Integrated Approach For Environment Problem & its Effect (Dr. Kanti Pachori) 68

29. Symbolism in the poetry of W.B. Yeats (Dr. Pratibha Rajpoot) 72

30. भारत और वैश्वीकरण – सामाजिक और राजनीतिक सन्दर्भ (डॉ. उमेद प्रसाद विश्वकर्मा) 74

31. मनुष्य के जीवन मे जैव विविधता का महत्व (डॉ. दयाराम साहू) 78

32. आर्थिक विकास में कृषि जैव विविधता का महत्व (डॉ. दयाराम साहू) 81

33. कोल इण्डिया लिमिटेड में प्रशिक्षण की भूमिका (डॉ. दीपचंद भावंरकर) 85

34. कार्यस्थल पर अच्छे वातावरण का महत्व कोल इण्डिया लिमिटेड के संदर्भ में (डॉ. दीपचंद भावंरकर) 87

35. जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकंन (विश्लेषणात्मक अध्ययन) (डॉ. राजेश कुमार लोखण्डे) 89

36. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ और कमियाँ (डॉ. राजेश कुमार लोखण्डे) 92

37. प्रसिद्ध कहानियों पर बनी हिन्दी फिल्मों का आकलन (डॉ. मजीद कुरैषी) 94

38. सामाजिक चेतना के कारकों के निर्धारण में वैश्वीकरण का प्रभाव (डॉ. उमेद प्रसाद विश्वकर्मा) 99

39. छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीतियों का जनजातियों पर प्रभाव – एक अध्ययन (जैनेन्द्र कुमार पटेल) 104

40. Agonies of the times author lived in and the subsequent manifestation of violence in the novels of Ernest Hemingway (Haroon Bashir Kar) 106

41. Human Resource Information System: An Innovative Strategy for Human Resource Management (Dr. Aalok Kumar Yadav) 108

42. महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य (डॉ. बी. के. गुप्ता) 111

43. गैरतगंज ब्लाक में कृषि का निदानात्मक अध्ययन (रत्नेश नारायण श्रीवास्तव) 113

44. Stress Management (Dr. Anita Dani) 115

45. भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी एवं सहयोग की भूमिका (डॉ. आराधना शुक्ला, निधि श्री) 117

****

भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी एवं सहयोग की भूमिका

डॉ. आराधना शुक्ला* निधि श्री**

शोध सारांश – भारत में निवेश के लिए विदेशी व्यक्तियों अथवा कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये पूंजी को विदेशी पूंजी कहते है, विदेशी पूंजी शब्द एक व्यापक शब्द हैं, जिसके अंतर्गत , 1. विदेशी सहायता , 2. व्यापारिक ऋण , 3. विदेशी निवेश को सम्मिलित किया जाता है। किसी देश की उत्पादक क्रियाओं में विदेशी सरकार, विदेशी निजी व्यक्ति व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए गए पूँजी निवेश (विनियोग) को विदेशी पूँजी कहते हैं। किसी भी विकासशील देश के विकासात्मक परियोजनाओं की सफलता विदेशों से प्राप्त अनुदान एवं प्राप्त रियायती ऋणों पर निर्भर करता है क्योंकि इन योजनाओं के लिए विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे आसानी से विदेशी सहायता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, विदेशों से प्राप्त अनुदान को वापस नहीं करना होता है , तथा रियायती ऋणों पर ब्याज की दर काफी कम होती है, और इसे वापस करने की अवधि बहुत लम्बी होती है। इस शोध पत्र में यह अध्ययन करने का प्रयास किया गया है कि विदेशी पूँजी का भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार अहम् भूमिका रही।

शब्द कुंजी – विदेशी सहायता, आर्थिक सहायता।

प्रस्तावना – भारत एक विकासशील देश है, जिसके आर्थिक विकास हेतु आधारभूत संरचना योजनागत व्ययों के लिए वृहत निवेश की आवश्यकता है, जिसे भारतीय निजी एवं सरकारी निवेश के द्वारा पूर्ति नही किया जा सकता, इस हेतु विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है, विदेशी पूंजी के द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक विशाल पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है, सामान्यतया विदेशी व्यक्तियों एवं कंपनियों के द्वारा आवश्यक पूंजी को उपलब्ध कराना ही विदेशी पूंजी कहलाता है, जो विदेशी सहायता, विदेशी निवेश या व्यापारी के रूप में हो सकती है।

विदेशी सहायता – विदेशी पूंजी का वह रूप है, जो विकसित देशों की सरकारों, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विकासशील देशों के आर्थिक विकास की दर को तीव्र गति प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

व्यापारिक ऋण – जब विदेशी सहायता से प्राप्त राशि किसी देश के विकासात्मक योजनाओं को गति प्रदान करनें में अपूर्ण होती है तो ,विदेशी बैंको से बाजार में प्रचलित ब्याज दर पर ऋण लिए जातें है, साथ ही साथ भारत के बैंको में अनिवासी भारतीयों के जमा राशि को विकासात्मक योजनाओं में प्रयोग किया जाता है, जिसे व्यापारिक ऋण कहतें हैं। उक्त दोनों विदेशी पूंजी योजनागत परियोजनाओं हेतु वांछित व्यय की राशि को पूर्ण नही कर पाते हो तो, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग जिसके अंतर्गत विदेशी नागरिक अथवा संगठन दूसरे देश मे अपनी पूंजी द्वारा उत्पादन इकाई स्थापित करता है या फिर विदेशी कंपनीयां , पोर्ट फोलियों निवेश के द्वारा भारतीय कंपनियों के अंश खरीदकर विनियोग करती है, इस प्रकार ये दोनों ही रास्ते **विदेशी विनियोग** माने जाते है, भारत जैसे विकासशील देशों में जहां आर्थिक विकास हेतु आवश्यक पूंजी एवं आधुनिक तकनीकी का अभाव है, वहां पर तकनीकी पूंजी संजीवनी का कार्य करती है। भारत मे नयें आर्थिक सुधारों के लिए विदेशी पूंजी कारगार सिद्ध हुई है, 1991 में आर्थिक सुधारों के पश्चात् भारत में विदेशी तकनीकी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निरंतर वृद्धि हुई है। जुलाई–अगस्त, 1991 में घोषित उदार विदेशी नीति के परिणमस्वरूप, विदेशी सहयोग के समझौतों में तथा विदेशी निवेश में तेज वृद्धि हुई है। **क्षेत्रानुसार में विदेशी तकनीकी स्थानांतर सहयोग अनुमोदित**, 1991 से अगस्त, 2011 के बीच सर्वाधिक तकनीकी सहयोग का अनुमोदित बिजली उपकरण (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) को 15 प्रतिशत हुआ था, उसके बाद क्रमशः रसायन (11.20%), औद्योगिक मशीनरी (10.79%), परिवहन उद्योग (9.36%), विविध इंजीनियरिंग उद्योग 5.50% किया था। भारत सरकार ने विदेशी सहयोगों को बढावा देने के लियें कई प्रयास किये हैं। इसके लिये कुछ क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी क्षमता निवेश की सहमती दे दी गयी , तथा विदेशी पूँजी के फलस्वरूप हमारा राष्ट्रीय आय का 5 प्रतिशत थी जो बढकर 1989-90 में 22 प्रतिशत और 2007-08 में 33 प्रतिशत हो गयी। 1970 के दशक से ही देश को विदेशी मुद्रा के संकट का सामना करना पडता है, इस संकट को दुर करने और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने मे विदेशी सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विदेशी पूँजी व सहयोग ने देश मे भारी व आधारभूत उद्योगो की स्थापना, परिवहन, संचार व विद्युत उत्पादन का विस्तार करके जहाँ एक ओर देश में औद्योगीकरण के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया हैं, वहीं दूसरी ओर देश के महत्वपूर्ण उद्योगों में विदेशी पूँजी विनियोग के द्वारा औद्योगिक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका हैं। देश को विदेशी पूँजी के अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ, भारतीयों को प्रशिक्षण की व्यवस्था और तकनीकी परामर्श के साथ साथ अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन मिला है।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) गुरूकूल महिला महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी,पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

परिवहन व संचार के साधनों के विकास में विदेशी पूँजी का सहयोग होता है। कुल विदेशी पूँजी का 14 प्रतिशत भाग परिवहन व संचार के विकास पर व्यय किया गया है। इनमें से 12 प्रतिशत व्यय रेल परिवहन के विकास पर हुआ। किसी भी देश के आर्थिक विकास में लोहा व इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्वतन्त्रता–प्राप्ति के समय भारत में यह उद्योग अविकसित अवस्था में था, किंतु आज हम लोहे का निर्यात कर रहे हैं। निर्माण उद्योगों के लिए किया गया है पश्चिमी जर्मनी , रूस तथा ब्रिटेन ने इस उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विश्लेषण – भारत में विगत वर्षों में विदेशी निवेश की प्रवृत्ति निम्न है :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
विदेशी निवेश:	42,127	39,231	46,710	26,386	38,385
(क) एफ.डी. आई	11,834	22,061	19,819	21,564	16,183
(ख) पोर्ट फोलिया निवेश:	30,293	17,170	26,891	4,822	22,202

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि बढता हुआ विदेशी निवेश भारत के बहुमुखी आर्थिक विकास हेतु संजीवनी का कार्य कर रहा है। भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी निवेश ने भारी उद्योगों की स्थापना की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा खाद्य संकट हल करने, सिंचाई एवं बिजली क्षमता का विस्तार करने, रेलवे का विकास करने, तकनीकी विकास एवं प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त करने में काफी सहयोग दिया है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी एवं सहयोग की भूमिका निभा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. एस.के.सिंह , व्यावसायिक पर्यावरण , साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
2. डॉ. मिश्र एवं शुक्ल, व्यावसायिक पर्यावरण, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
3. डॉ. वी.सी. सिन्हा, व्यावसायिक पर्यावरण, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
4. प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक अर्थशास्त्र
5. रमेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था, मेक ग्रीव हील एजुकेशन

****

January to March 2018
E-Jouenal, Volume IV, Issue XXI
U.G.C. Journal No. 64728

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.1 [illegible] 017)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
(U.G.C. Approved Journal)

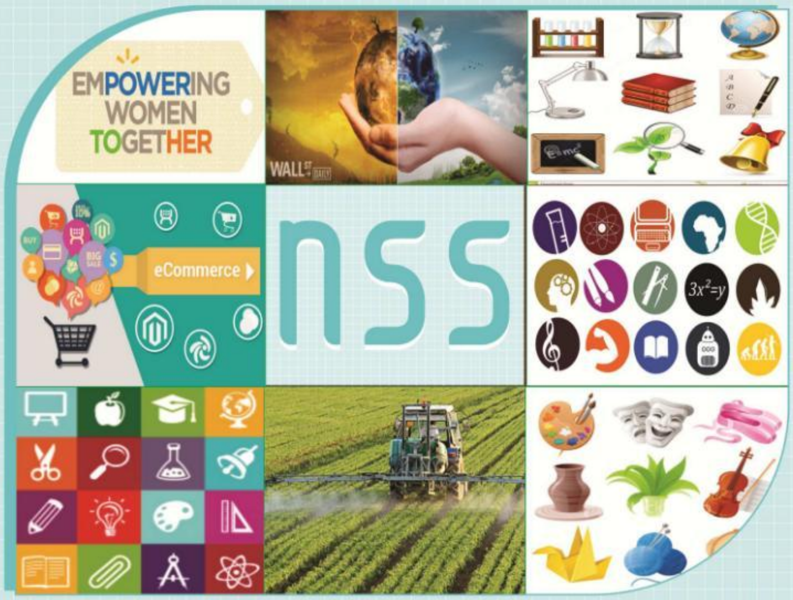

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

243. भारत की गरीबी निवारण योजनाओं का मूल्यांकन (डॉ आराधना शुक्ला, निधी श्री) 725
244. रामायण और आधुनिक काल में दाम्पत्य की अवधारणा व स्वरूप (डॉ. अभयवीर) 727

भारत की गरीबी निवारण योजनाओं का मूल्यांकन

डॉ. आराधना शुक्ला* निधी श्री **

शोध सारांश – भारत देश में गरीबी आर्थिक विकास में सबसे बडी बाधा बनती जा रही है अत: विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन के पूर्व सरकार के द्वारा गरीबी निवारण अनेक योजनायें संचालित की जा रही है। ताकि जनता के पास क्रय शक्ति सृजित हो और उनके द्वारा देश के आर्थिक विकास के आवश्यक पहलू बचत व निवेश पर योगदान दिया जा सके।

शब्द कुंजी – गरीबी, आर्थिक विकास एवं गरीबी निवारण योजनायें।

प्रस्तावना – कोई भी देश आर्थिक गति तभी पास कर सकता है जब उस देश की जनता के पास पर्याप्त आय प्राप्ति के साधन हो कि वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। किन्तु भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व गरीबी अथवा निर्धनता है अत: देश की सरकार का सर्व प्रथम दायित्व जनता की गरीबी हटाना होता है। गरीबी निवारण हेत सरकार अनेक योजनायें संचालित कर रही है जो मुख्य रुप से जनका को न केवल आय क साधन प्रदान कर रही है बल्कि उन्हे स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। जैसे :- मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, इंदिरा आवास योजना, जनश्री बीमा योजना, अंत्योदय अन्य योजना आदि।

गरीबी निवारण संचालित योजनाओं से गरीब जनता को आय एवं रोजगार प्राप्ति के अनेक स्त्रोत प्राप्त होते हैं तथा तथा कौशल विकास योजनाओं से जनता को आय व रोजगार की प्राप्ति होगी परिणाम स्वरुप बचत व निवेश भी प्रोत्साहित होंगे और देश का आर्थिक विकास संभव हो जायेगा।

अध्ययन का उद्देश्य – शोध पत्र अध्ययन के उद्देशय अग्रांकित है-

1. देश में गरीबी का अध्ययन करना।
2. संचालित विभिन्न गरीबी निवारण कार्यक्रमों की उपलब्धि का अध्ययन करना।
3. विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के गरीबी पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. विभिन्न गरीबी निवारण योजनाओं से गरीबी का स्तर कम हो रहा है।
2. गरीबी निवारण योजनायें देश की गरीबी हटाने में प्रभावकारी है।

शोध प्रविधि – भारत देश की सरकार के द्वारा संचालित गरीबी निवारण योजनायें वास्तव में गरीबी निवारण में प्रभावकारी है अपव्यय नहीं इस तथ्य के विश्लेषण हेतु भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा संचालित द्वितीयक आंकडो का अध्ययन किया गया है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन :

1. बालकृष्ण बी. 1943 इन्होने अनेक शासकीय योजनायें विशेषकर विपणन संबंधी योजनाओं पर अध्ययन कर यह निष्कर्ष प्रकट किया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की संरचना के आधार पर विपणन संबंधी योजनायें संचालित करती है।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय पोर्टल से प्रकाशन कॉलम के वार्षिक रिपोर्ट एवं पहल व उपलब्धियों के द्वारा हमे वर्तमान में चल रही सरकार की ग्रामीण विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई एवं इन गतिविधियों के ग्रामीण निर्धनो के उपर प्रभाव तथा उनके फायदे के बारे में जाना। यह जानकारी हमें हमारे रिर्सच पेपर हेतु बहुत ही सहयोगी रही है।

शोध अध्ययन – भारत में देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय कम होना ही यहां कि निर्धनता का प्रमुख कारण है। साथ साथ ही यह कहा जा सकता हैकि देश में गरीबी के प्रमुख कारण मुख्यत: रोजगार अवसरो में धीमी वृद्धि, निम्न आय अर्जन, जनसंख्या में भारी वृद्धि, दोषपूर्ण आर्थिक निति आदि रहा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं से ही देश में गरीबी निवारण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है उनका प्रभाव गरीबी निवारण पर प्रभाव दिखाई देने लगा है तथा गरीबी के आंकडों में दिन प्रतिदिन आंशिक सुधार हो रहा है जो अग्रांकित आंकडो से स्पष्ट हो रहा है:-

भारत में निर्धनता अनुपात एवं निर्धनो की संख्या

वर्ष	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)	निर्धनों की संख्या (करोड में)
2004-05	37.2	40.71
2009-10	29.8	35.47
2011-12	21.9	26.93
2014-15	24.5	36.93

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत देश में निर्धनता की अनुपात 2004-05 में 37.2 प्रतिशत तथा वह घटकर 2011-12 में 26.93 करोड रह गया किंतु 2014-15 में निर्धन अनुपात एवं निर्धनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण आर्थिक निती, मुद्रा प्रसार एवं मूल्य वृद्धि रही है।

सुझाव एवं निष्कर्ष – शोधकर्ता ने गरीबी निवारण संबंधी योजनाओं के सफल संचालन एवं परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्न सुझाव दिया है :-

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) आर. आई. टी. महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रगति महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

1. भारत जैसे कृषि प्रधान देश हेतु बहुफसली कार्यक्रम चलायं जाने चाहिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण से संबंधित योजनाओं जैसे सडक निर्माण, कुऑ, नहर, आवास, विद्युत संबंधित संचालित किया जाना चाहिए।
3. कौशल विकास योजनाओं का उचित तरीके से संचालन किया जाना चाहिए।
4. योजनाओं से संबंधित जानकारी जन समान्य तक सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ जे.पी. मिश्रा, 'व्यावसायिक पर्यावरण', साहित्य पब्लिकेशन, पेज क्रमांक 88-89
2. डॉ वी.सी. सिन्हा, 'व्यावसायिक पर्यावरण', संजय साहित्य पब्लिकेशन, पेज क्रमांक 208
3. 'भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण रिर्पोट'
4. सिन्हा वी.सी.,'राजस्व एवं रोजगार के सियांत', पेज क्रमांक 108-110
5. पुरी एवं मिश्रा,'भारतीय अर्थशास्त्र', पेज क्रमांक 69
6. WWW.FING.GOV.IN, INDIA

****

Volume III, Issue XXII
April 2018 E-Journal
U.G.C. Journal No. 64728

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.110 (2017)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
(U.G.C. Approved Journal)

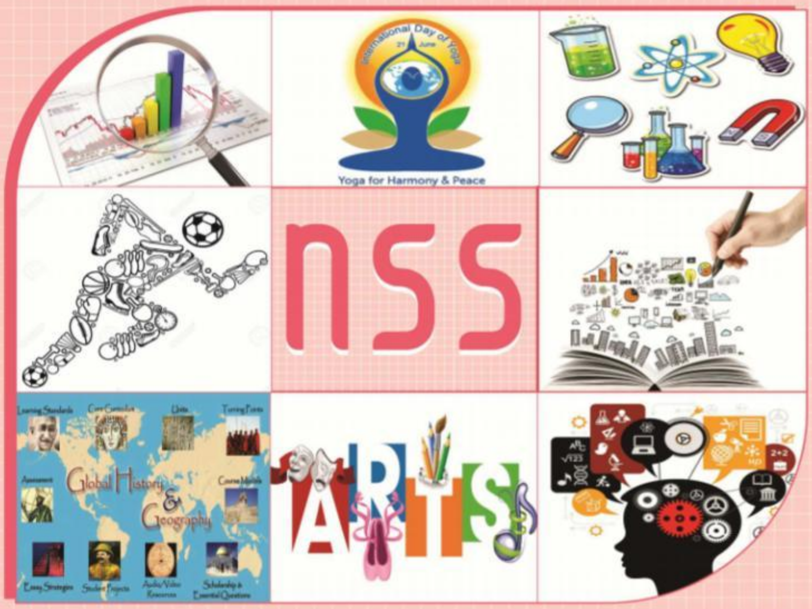

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

55. Concept And Application Of Promissiory Estoppel : A Critical Study With Indian Evidence 152
Act And Legislation (Narender Dhaka)

56. Relevance of Cashless Economy in India (Dr.Yadu Rao) 155

57. लघु उद्योगो के विकास में जिला उद्योग केन्द्र का योगदान (नन्दना शिल्पकार, डॉ. ए.के. पाण्डेय) 159

58. भारत में ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत (डॉ. शुभ्रा तिवारी) 161

59. पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच की भूमिका (धनेन्द्र कुमार, डॉ. वाय.बी. कसवे) 163

60. अलका सरावगी के कथा साहित्य में चेतना के विविध आयाम (सुनिता चौहान, डॉ. मंजुला जोषी) 165

61. Historical Analysis of Spread of Buddhism from India To Tibet (Dr. Shilpa Mehta) 167

62. भवन निर्माण में कार्यरत महिला श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मूल्यांकन (उषा राजे, डॉ. महेश गुप्ता) ... 170

63. कृषक की आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक अफीम (डॉ. प्रीति मुरड़िया) 172

64. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं भारत (डॉ. आराधना शुक्ला, निधी श्री) 174

65. Role of Management in Faculty Development (Dr. Prabhat Chopra) 175

66. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के मानवाधिकार (रवि प्रकाश चौधरी, डॉ. ए.बी. सोनी) 181

67. हिन्दी साहित्य में किन्नरों का यथार्थवादी चरित्र-चित्रण (डॉ. पिंकी मिश्रा) 183

68. Analytical Study Of Women Oriented Life Insurance Plans 185
(Dr. Savita Agrawal, Dr. Monika Bapat, Dr. Venus Shah)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं भारत

डॉ. आराधना शुक्ला* निधी श्री **

शोध सारांश – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों के वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को सहज बनाने मे सहायक है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य व अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के आर्थिक स्थिरता, गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

शब्द कुंजी – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

प्रस्तावना – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा -कोष की स्थापना प्रथम व द्वितीय महायुद्ध के मध्य की अवधि मे विद्यमान वित्तीय विषम परिस्थितियों का परिणाम था। जुलाई, 1944 में ब्रेटनवुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा - कोष की स्थापना की गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य – कोष के उद्देश्य, को चार्टर के अनुसार निम्न प्रकार बताये गये है :

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना – इस कोष का प्रथम उद्देश्य सदस्य देशों में मुद्रा नीति सम्बन्धी सहयोग स्थापित करना और मुद्रा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत एवं सहयोग से हल करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा – कोष का दुसरा उद्देश्य ऐसी सुविधाएँ जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढावा मिले, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, विनिमय दर में स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की विशमता को दूर करना, विनिमय नियंत्रण को हटाना, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान असन्तुलन को कम करना, उत्पादक पूँजी विनियोग, असन्तुलित आर्थिक विकास में सहायक। भारत का मुद्रा-कोष से घनिष्ठ सम्बन्ध है, तथा मुद्रा - कोष नीति-निर्माण एवं कार्य-संचालन मे भारत निरन्तर योगदान रहा है।

तालिका 1 - (निचे देखे)

31 मार्च, 2002 के बाद भारत में ने मुद्रा - कोष से कोई ऋण नही लिया है। 23 अक्टुबर, 2010 जी-20 के वित मंत्री के बैठक में कई सहमती बनी, बैठक के बाद भारत के वित मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आईएमएफ में भारत की रैंक तीन अंक ऊपर हो जाएगी, भारत आठवें स्थान पर आ जाएगा, मुखर्जी ने कहा, 'हमने महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है, आईएमएफ में अब भारत का कोटा 2.75 फीसदी बढ़ गया है, इससे पहले भारतीय हिस्सेदारी 2.44 फीसदी थी।

आईएमएफ में एशिया प्रशांत विभाग के उप निर्देशक केनेथ कांग ने कहा कि एशिया का परिदृष्य अच्छा है और यह मुश्किल सुधारों के समिप भारत को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के लिए त्रिवक्षीय ढांचागत सुधार दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया, 7-09 अक्टूबर, 2016 में हुए बैठक मे यह निष्कर्ष सामने आता है कि भारत की चरम गरीबी एवं भ्रष्टाचार को 2030 तक विश्व बैंक के मिशन तहत समाप्त करना है, युवाओं का उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, आर्थिक असामनताओं को दूर करने हेतु अनेक सरकारी प्रयास किये जाने चाहिए, वैश्वीकरण एवं प्रौद्योगिकीकरण हेतु भारत में कार्य किये जाना आवश्यक हो गया है, तथा महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाओ को संचालित करते हुए अनेक योजनाओ को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग कॉग का कहना है कि भारत में आर्थिक विकास एवं विनियोग के प्रत्याय दर तीव्र गति से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि यह एक बहुल संसाधन देश हैं, 27 जनवरी, 2016 के कोटा समीक्षा में भारत का कोटा बढ़कर 2.78 प्रतिशत हो गया है, तथा मताधिकार बढ़कर 2.66 प्रतिशत हो गई है, इस प्रकार यह संकेत प्राप्त हो रहा है कि, भारत चहुमुखी आर्थिक विकास कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ओझा शिवकुमार, भारतीय अर्थव्यवस्था बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. सिन्हा वी.सी., व्यावासायिक पर्यावरण, एस.बी.पी.डी.,पब्लिकेशन हाउस।
3. प्रतियोगिता दर्पण।

तालिका 1

वर्ष	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
कुल ऋण	2623	3451	4799	5040	4300	2374	1313	664	287	26

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) आर. आई. टी. महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रगति महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

Certificate of Publication

is hereby granted to CERT-16159/18-19

MRS. NIDHI SHRI SHUKLA

for authoring and publishing the research paper titled

CONTRIBUTION OF INDUSTRIAL SECTOR'S IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN INDIA

in

JOURNAL OF ADVANCES AND SCHOLARLY RESEARCHES IN ALLIED EDUCATION

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

IMPACT FACTOR : 3.46

VOL- 15, ISSUE- 1 **ISSN: 2230-7540**

Awarded **02-Apr-2018**

CHAIR
RESEARCH LAISION DIV.

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC Approved Journal

IAO

IGNITED MINDS Journals

The manuscript is published at URL: http://www.ignited.in/

Volume I, Issue XVIII
October To December 2019

ISSN 2391-3807
E-ISSN 2394-3513
Impact Factor - 5.190

Divya Shodh Samiksha

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

दिव्य शोध समीक्षा

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email :** dssresearchjournal@gmail.com, **Website :** www.dssresearchjournal.com

25. Education System of India and it's Drawback (Kartikeswar Patro) 71

26. Economic Condition Of The People During The Gupta Period (Sunil Sharma) 74

27. Jammu And Kashmir Reorganisation Act 2019 - Sign Of A New Change 76
(Jai Prakash Vyas, Prof. (Dr.) Yogendra Shirivastav)

28. Mansabdari System During Mughal Rule (Sunil Sharma) 79

29. Isolation and Characterisation of a Novel Flavonoid Glycoside from the Stem of 81
Impatiens Scabrida D.C. (Dr. Basanti Jain)

30. निमाड़ के 17वीं-18वीं सदी के सन्तों द्वारा साहित्य सृजन (डॉ. मधुसूदन चौबे) 83

31. हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति (डॉ. आर. एस.वाटे) 86

32. सभी किसानों की कर्जमाफी देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। (म.प्र. के सदर्भ में) (डॉ. दीपक जैन) .. 89

33. Skill-Development Programme & Self-Employment Opportunity In Chhattisgarh 91
(Mrs. Nidhi Shri Shukla, Dr. Aradhna Shukla)

34. Copyright Agreement Form 93

35. Research Paper Making Process 94

****

Skill-Development Programme & Self-Employment Opportunity In Chhattisgarh

Mrs. Nidhi Shri Shukla Dr. Aradhna Shukla*

Abstract - Chhattisgarh has gradually evolved as a knowledge-based economy due to the abundance of capable and qualified human capital. With the constantly rising influence of resources, Chhattisgarh has immense opportunities to establish its distinctive position in the India. However, there is a need to further develop and empower the human capital to ensure the chhattisgarh's national competiveness. Despite the stress laid on education and training in this country, there is still a shortage of skilled manpower to address the mounting needs and demands of the economy.
Keywords - Skill-development and self-employment opportunity in chhattisgarh.

Introduction - The focus is to skill the youths in such a way so that they get employment and also improve self-employment. Provides training, support and guidance for all occupations that were of traditional type like carpenters, cobblers, welders, blacksmiths, masons, nurses, tailors, weavers etc. More emphasis will be given on new areas like real estate, construction, transportation, textile, gem industry, jewellery designing, banking, tourism and various other sectors, where skill development is inadequate or nil.

Objectives :
1. Key sectors for focus for skill development for better employment & livelihood(self-employment) in state.
2. Major livelihood sectors & key growth sector of state.
3. Level of skill required to met the demand of economic stability.

Hypothesis
1. There are sectors on whichchhattisgarh govt. has to focus on skill development for better employment & livelihood(self-employment) in state on the basis of required man-power.
2. Study proven data that has major livelihood sectors & key growth sector in state for human resource.

Research Methodology - This research study is based on secondary data obtained from Chhattisgarh planning commission for development.

Research Analysis - Our topic is " **Skill-develepment and self-employment opportunity in chhatisgarh.**" for which data related to key sectors, required human resources are taken from planning commission(CSSD) of C.G. Analysis is done with the help of or on the basis of available data through tables which are as follows:-

HR Requirement By 2015 Based On Cii Survey:-

Key Sector	Major Livel ihood Sectors	Skill Level	HR Required
Power	Agriculture/food processing	Minimum education skill	6.50lac
Mining/ minerals	Forest/forest produced based industry	ITI & diploma certification	5lac
Steel/ cement	Rural industry sector	Graduates	4.10lac
Construction	-	Specialized skill	0.64lac
Service Sector	-	-	-
Education	-	-	-
		TOTAL	16.40lac

HR Requirement Based On Mou's Signed With Upcoming Industries

Category	Mining	Power	Sponge/ Iron/ Cement	Total
Managerial	450	10000	7750	18200
Supervisory	2200	25000	12250	39450
Skilled	8350	40000	22600	70950
Unskilled	4400	10000	35000	49400
In-direct	-	200000	-	200000
TOTAL	15400	285000	77600	378000

By the above table major key sectors are 6 ,major self-employment sectors are 3 and the skill level sector wise gives enlarge view of requirement of man-power which is markably possible by the skill-development & self-employment programme of the state.

Conclusion - Thereby analysis and research studythe key sectors and major self-employment area's are of great impact on required human resources which ultimately hits the skill development programme and self-employment

*Asst. Professor (Commerce) Vipra Arts, Commerce and Physical Education College, Raipur (C.G) INDIA
** Asst. Professor (Commerce) Vipra Arts, Commerce and Physical Education College, Raipur (C.G) INDIA

opportunity in Chhattisgarh which finally lead the subject matter as well as the structure of different C.G. skill development and self-employment programme released by the C.M. of Chhattisgarh which under the flagship of 9 departments which undertakes 26 skill-development& self-employment programme in the 22 sectors of Chhattisgarh.

References :-

1. HR REQUIREMENT BY 2015 BASED ON CII SURVEY-C.G. Govt. booklet.
2. RURAL SKILL DEVELOPMENT: ISSUES AND CHALLENGES IN CHHATTISGARH-Rashmi Dewangan (Asst. prof. ,Shankracharya Mahavidyalaya Bhilai).
3. SKILL DEVELOPMENT FOR SELF EMPLOYMENT-Glory Swarupa(Research Scholar) & Ravi Kumar Goyal (Guid & Principal ,School Of Enterpreneurship ,BSDU,Jaipur).
4. SKILL DEVELOPMENT, EMPLOYMENTABILITY AND ENTERPRENEURSHIP THROUGH MAKE IN INDIAA STUDY- Dr. Jagdish Prasad, Asst. Dir. At directrare of technical education & Dr. DGM Purohit, Prof.JNV university jodhpur,Rajasthan.
5. IMPROVISING SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYABILITY POTENTIAL THROUGH HIGHER EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION IN INDIA-Seema pandey, Prof. JECRC Jaipur Rajasthan.

****